



RNI No. MAHBIL/2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १५]

सोमवार, जुलै ९, २०१८/आषाढ १८, शके १९४०

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३० प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ९ जुलाई, २०१८ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. A. BILL No. XLII OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४२ सन् २०१८।

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९०८ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, २०१८, २७ जून, २०१८ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है:-

१. (१) यह अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन), अधिनियम, २०१८ कहलाए।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) यह २७ जून २०१८ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

महाराष्ट्र राज्य में
यथा प्रयुक्त, सन्
१९०८ का ५ की
धारा ९क का
अपमार्जन।

व्यावृत्तियाँ।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” सन् १९०८ का ५। कहा गया है) की धारा ९क, अपमार्जित की जायेगी।

३. मूल अधिनियम की धारा ९ क के अपमार्जन के होते हुये भी,—

(१) जहाँ, धारा ९क के अधीन विरचित प्रारम्भिक विवाद की विचारणा, सिविल प्रक्रिया संहिता सन् १९०८ का ५। (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१८ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में “संशोधन अधिनियम” कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक पर प्रलंबित हैं, वहाँ, उक्त विवाद, मूल अधिनियम के आदेश चौदह के अधीन विरचित विवाद समझा जायेगा और वाद के अपने अंतिम निपटान के समय पर सभी अन्य विवादों के समेत, जैसा कि उचित समझा जाये, न्यायालय द्वारा, विनिश्चित किया जायेगा :

परंतु, धारा ९क के अधीन, इस प्रकार विरचित प्रारम्भिक विवाद पर, वाद के लिये, सबूत, यदि किन्ही हो, किसी पक्ष या पक्षों ने प्रस्तुत किये हैं, तब वाद के उसके अंतिम निपटान के समय पर, वाद में के अन्य विवाद्यों पर प्रस्तुत, सबूत, यदि किन्ही हो, के समेत, न्यायालय द्वारा, ध्यान में लिया जायेगा ;

(२) सभी मामलों में, जहाँ, धारा, ९क के अधीन विरचित प्रारम्भिक विवाद, वाद पर विचार करने की अधिकारिता न्यायालय को हैं, धारण करते हुये, विनिश्चित किया गया है और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसे विनिर्णय पर आपत्ति उठाना, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर प्रलंबित हैं, ऐसी पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ समाप्त होंगी :

परंतु, ऐसे विवाद में न्यायनिर्णय, अधिकारिता धारण करने वाले आदेश में, किसी चूक, दोष या अनियमितता के कारण अपील किया गया है, वहाँ, अपील के ज्ञापन में, यदि ऐसे ज्ञापन में सम्मिलित है के रूप में आपत्ति के आधार पर में से एक हो, ऐसे विवेचित किया जायेगा ;

(३) सभी मामलों में, जहाँ, धारा, ९क के अधीन विरचित प्रारम्भिक विवाद, वाद पर विचार करने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं हैं, धारण करते हुये, विनिश्चित किया गया है और अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसे विनिर्णय पर आपत्ति उठाना, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर, प्रलंबित, हैं, ऐसी अपीलीय या पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ, जैसे कि, संशोधन अधिनियम, अधिनियमित नहीं किया गया है और धारा ९क अपमार्जित नहीं हुई हैं, निरंतर रहेगी :

परंतु, धारा ९क के अधीन, इस प्रकार विरचित प्रारम्भिक विवादों के पुनर्विचारण के लिये परीक्षण न्यायालय को ऐसी अपील या पुनरीक्षण प्रतिप्रेषित करना, परीक्षण न्यायालय द्वारा, इन कार्यवाहियों की प्राप्ति पर भागतः अनुमत किये जाने के दौरान, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के मामलों में, मूल अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

(४) सभी मामलों में, जहाँ, धारा ९क, उसके अपमार्जन के पूर्व की उप-धारा (२) के अधीन, अंतरिम राहत मंजूर करनेवाला आदेश, मंजूर किया गया है, वहाँ, ऐसा आदेश, मूल अधिनियम का आदेश ३९ के अधीन बनाया गया अंतरिम आदेश समझा जायेगा और, न्यायालय, आवेदन, जिसमें, ऐसा आदेश बनाया गया है को विनिश्चित करने के समय पर, ऐसा आदेश या तो, निश्चित या रद्द या रूपांतरित करेगा।

४. (१) सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, २०१८ एतद्वारा, निरसित किया सन् २०१८ का ५। जाता है। अध्या. क्र. २८।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् २०१८ का
महा. अध्या. क्र.
१८ का निरसन
तथा व्यावृत्ति।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र राज्य में, यथाप्रयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता [(महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९७० (सन् १९७० का महा. २५) द्वारा, इंडो-पोर्तुगीज संस्था बनाम बोर्जस् (१९५८) ६०, बम्बई, एल. आर. ६६०)] के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के प्रभावों को मिटाने की दृष्टि से, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सन् १९०८ का ५), में धारा ९क निविष्ट की गयी थी।

उस समय, जब, उक्त संहिता की धारा ८० के अधीन जारी की गई विधिमान्य सूचना के बिना, बम्बई शहर सिविल न्यायालय में, सरकार के विरुद्ध वाद दर्ज किया गया था, तब, न्यायालय ने, अधिकारिता का प्रश्न उठाये बिना, अंतरिम आदेश मंजूर किया था और वादी को स्थगन दिया था। इससे, वादी को सरकार को सूचना जारी करने में समर्थ बनाया था। सूचना की अवधि के अवसान के पश्चात्, वादी, तब स्वतंत्रता से वाद पिछे ले कर एक नया वाद दर्ज करा सकता था और नये रूप से दर्ज वाद में, पूर्वतर मंजूर किये गये अंतरिम आदेश निरंतर रखा जा सकता था।

इसलिए, ऐसा महसूस होता है कि, अधिकारिता का प्रश्न उठाए बिना, जब कि उठाया गया हो, तब भी आदेश मंजूर करने की प्रथा का गंभीर दुरुपयोग हो रहा है। यह पृष्ठपट के विरुद्ध है कि, उक्त संहिता में धारा ९क पुरःस्थापित की गई थी।

२. सन् १९७६ में, संसद द्वारा अधिनियमित, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९७६ (सन् १९७६ का १०४) द्वारा, उक्त संहिता व्यापक रूप से, संशोधित की गई है। इसलिए, आशंका की कोई भी जगह न हो, चाहे राज्य संशोधन निरंतर प्रवृत्त है या निरसित हुये हैं, के लिये, सन् १९७० का महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, निरसित किया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९७७ (सन् १९७७ का महा. ६५) द्वारा धारा ९क फिर से पुनः अधिनियमित की गई थी।

३. तथापि, न्यायिक अनुशेष के लिए और कई जटिलता बढ़ाने के लिए सहायक हुई धारा ९क के उपबंध बोझिल और नीरस बन गए हैं। मेहेर सिंह बनाम दिपक सोवनी, [(१९९८) ३ एमएच. एल. जे. ९४०] में यह निर्णय लिया गया है कि, जहाँ, अधिकारिता के वाद में तथ्य और विधि का मिश्र प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं, वहाँ, पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। फोअरशोअर सहकारी आवास संस्था बनाम प्रविण डी. देसाई [(२०१५) ६ एसएससी ४१२ और संदीप गोपाल रहेजा बनाम सोनाली निमिष अरोरा (२०१६) एसएससी लाईन बम्बई। ९३७८ पर] में यह निर्णय दिया गया है कि, धारा ९क प्राकृतिक रूप से अनिवार्य हैं, जहाँ, न्यायालय की अधिकारिता पर प्रतिवादी आपत्ति उठाता है और न्यायालय को कोई विवेक नहीं है और विवादय विरचित करने और उसे विनिश्चित करने के लिये बाध्य हैं। मुकुंद लिमिटेड बनाम मुंबई आंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, [(२०११) २ महा. एलजे ९३६]] में यह निर्णय लिया गया है कि, मुकदमेबाजी की नीति के रूप में, प्रतिवादी, भी, अंतरिम आवेदन की सुनवाई पर उसकी अधिकारिता विषयक आपत्ति नहीं लेने का विनिश्चय नहीं कर सकेगा। चाहे, धारा ९क में, प्रतिवादी द्वारा निवेदन समाविष्ट है या नहीं का प्रश्न कि, परिसीमा की विधि द्वारा वाद बाधित है, वह विवादास्पद में से एक है, जो, दिनांकित १७ अगस्त, २०१५ के आदेश के आधार पर, जगदीश श्यामराव थोरवे बनाम श्री. मोहन सिताराम द्रविड, एसएलपी (सी) २२४३८/२०१५, में उच्चतम न्यायालय के बड़े न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट किया गया था।

परिणामस्वरूप, उक्त संहिता की धारा ९क ने, कम-से-कम दो न्यायिक अवरोध बढ़ाये हैं, जिससे, मामलों के शीघ्रगति निपटान में बाधा डाली है। प्रथमतः जब, संहिता की धारा ९क के अधीन वाद उठाया जाता है, तब न्यायालय, परीक्षण, जिसमें ऐसा वाद समाप्त नहीं होता है और वाद अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाता है, तब तक, प्रावेदन का निपटान नहीं कर सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप, प्रावेदन कई वर्षों के लिए प्रलंबित रह जाता है, और अंतरिम राहत वस्तुतः अंतिम राहत के रूप में ढोंग लेती है। दूसरा यह कि, जब ऐसा वाद उठाया जाता है, दो परीक्षण संचालित करने होते हैं, जैसे, एक प्रारम्भिक वाद पर और अन्य शेष वादों पर, प्रत्येक उसके अपने अपीलों की संख्या और विशेष अवकाश याचिका के अध्यधीन होते हैं। यह सभी अनावश्यक रूप से, द्विरावृत्ति के साथ, न्यायालय पर बोझ डालती है और परिणामिक न्यायिक समय और स्रोत व्यर्थ हो जाते हैं। वास्तव में,

माधुरीबेन के. मेहता बनाम आश्विन रुपसी नायडू, [(२०१२) ५ बम्बई सी. आर. २७] में, बम्बई उच्च न्यायालय के ध्यान में आया है कि, उक्त धारा ९ क, “ दोहराए गये आवेदनों द्वारा, द्विरावृत्ति के काम का दुरुपयोग बढ़ाती है, जो स्थानिक रूप से चक्करदार प्रथा हैं । ”।

४. उक्त धारा ९क के अपमार्जन द्वारा, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

५. प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर न्यायालय में लम्बित कार्यवाहियों पर उक्त धारा ९क के अपमार्जन और के परिणामस्वरूप उपबंध करने के लिए अवसर भी लिया जा रहा था। उपबंध करने के लिए प्रस्तावित था कि,—

(क) उसके बाद के अंतिम निर्णय के समय में विनिश्चय किये जानेवाले उस संबंध में पहले ही साक्ष के विचार-विमर्श समेत सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश १४ के अधीन विरचित अन्य विवाद्य विषय के साथ लम्बित प्रारम्भिक विवाद्य विषय ;

(ख) विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण मंच के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण का उपशमन यह धारण करता है कि वाद के ग्रहण करने की अधिकारिता है ताकि यदि वाद अंतिम निर्धारित (डिक्रीड) है के मामले में अपील स्तर में अधिकारिता के विवाद्य विषय पर निष्कर्षों की चुनौती के लिए प्रतिवादी के अधिकार सक्रिय रखते समय स्वयं वाद के तत्काल और अंतिम निपटान सुनिश्चित किया जा सके ;

(ग) विचारण न्यायालय के निर्णय विरुद्ध अपील न्यायालय के समक्ष लम्बित अपीलों का जारी रहना यह धारणा करता है कि वाद के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है मानों कि उक्त धारा ९क अपमार्जित नहीं की गई है, ऐसे मामले में स्वयं वाद अंतिमतः खारिज किया गया है ;

(घ) उपबंध है कि उक्त धारा ९क की उप-धारा (२) के अधीन अनुदत्त उसके अपमार्जन के पूर्व अंतरिम राहत सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश ३९ के अधीन किये गये अंतरिम आवेदन में अंतरिम आदेश के रूप में माना जायेगा जो अंतरिम आवेदन की अंतिम सुनवाई में पृष्टिकारक या रिक्त हो सकेगा।

६. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सन् १९०८ का महा. ५) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, २७ जून, २०१८ को सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (सन् २०१८ का महा. अध्या. क्र. १८) प्रख्यापित किया गया था।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

नागपुर,
दिनांकित ५ जुलाई, २०१८।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित ९ जुलाई, २०१८।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।